भारत में दूरसंचार परिदृश्य

भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक अभिन्न घटक, ई-क्रांति के कार्यान्वयन का लक्ष्य ‘‘शासन में परिवर्तन के लिए ई-गवर्नेंस रूपांतरण’’ है और यह देश में ई-गवर्नेंस, आसान शासन और बेहतर शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात पर बल दिया है कि ई-गवर्नेंस का अर्थ है, आसान शासन, कारगर शासन और किफायती शासन। आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अद्यतन आविष्कारों ने ई-गवर्नेंस को बेहतर शासन के युग में प्रवेश के लिए एक सक्षम साधन बना दिया है। माईजीओवी प्लेटफार्म, जीवन प्रमाण, वाईफाई हॉटस्पॉट, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीओ, डाक घरों के जरिए ई-कामर्स आदि ई-गवर्नेंस परियोजनाएं एक ऐसी मौन इलेक्ट्रोनिक क्रांति की शुरुआत मात्र हैं जिसका लक्ष्य नागरिकों और व्यापारिक संगठनों को इलेक्ट्रोनिक पद्धति से सरकारी सेवाएं वितरित करना ताकि एक ऐसी पारिस्थितिकी प्रणाली को मजबूत किया जा सके जो डिजिटल दृष्टि से समावेशी, सुदृढ़ और समानता पर आधारित विकास सुनिश्चित करेगी। ये सभी ई-गवर्नेंस के उद्देश्य और लोकाचार हैं। ई-गवर्नेंस से संबंधित इन परियोजनाओं के लिए सरकार से नीतियों, दिशा-निर्देशों और फ्रेमवर्कों के जरिए आवश्यक सहायता अपेक्षित है।

इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीइट वाई) ने हाल ही में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई नीतिगत उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा, ई-क्रांति, ओपन सोर्स साफ्टवेयर, ओपन एपीआईज़, ई-मेल पालिसी, आईटी संसाधनों का उपयोग, संयुक्त अप्लीकेशन डिवेलपमेंट और अनुप्रयोग विकास तथा क्लाउड रेडी अप्लीकेशंस के लिए री-इंजीनियरिंग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन नीतिगत उपायों से सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उभरती प्रौद्योगिकियों से सही

अर्थों में मदद मिलेगी, नए व्यापार मॉडलों का उपयोग किया जा सकेगा और मौजूदा परियोजनाओं का जीर्णोद्धार हो सकेगा ताकि नागरिकों को एक सक्षम पारदर्शी और किफायती ढंग से इलेक्ट्रोनिक पद्धति से सेवाएं वितरित की जा सकें।

दूरसंचार विभाग ने जनसाधारण तक पहुंच कायम करने और कम लागत पर सेवा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने जुलाई 2015 से एक राष्ट्र-पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुरू की है। नागरिकों को इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार ने 2015-16 के दौरान देश में 2500 वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना बनाई है। बीएसएनएल अभी तक विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों और प्रमुख शहरों जैसे ताजमहल-आगरा, हुसैन सागर झील और चारमिनार-हैदराबाद, सारनाथ-वाराणसी, सूर्य मंदिर-कोणार्क, बृहदेश्वर मंदिर-तंजावुर, हम्पी-कर्नाटक, खजुराहो, जगन्नाथ मंदिर-पुरी, नाशिक, बंगलौर, विजयवाड़ा और बिलारपुर में वाईफाई हॉटस्पॉटस स्थापित कर चुका है।

डिजिटल अंतराल दूर करने के लिए सरकार ने 25 दिसंबर, 2014 को ज्ञान सेतु कार्यक्रम शुरू किया। इसका डिजाइन सी-डॉट ने तैयार किया है और यह इंटरनेट आधारित वास्तविक समय पर सेवाएं प्रदान करने वाली आईसीटी प्रणाली है जिसका प्रमुख लक्ष्य भारत की उपेक्षित ग्रामीण आबादी को विभिन्न प्रकार की ई-सेवाएं प्रदान करना है। ज्ञान सेतु, देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के फायदे ग्रामीण भारत तक पहुंचाएगा और शिक्षित, उच्च स्तरीय समाज और ग्रामीण समुदायों के बीच डिजिटल अंतराल दूर करेगा। इससे हमारे ग्रामीण इलाकों में सूचना और ज्ञान को लोगों की दहलीज पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में गहन डिजिटल प्रसार के लिए, सरकार ने भारतनेट की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों (60 करोड़ ग्रामीण

नागरिकों) को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा सकेगा। इससे ब्रा ॅडबैंक के प्रसार और ध्वनि प्रसार दोनों ही दृष्टियों से ग्रामीण कवरेज अंतराल दूर हो सकेगा। परियोजना का कार्यान्वयन भारत ब्रॉडबैंक नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जो इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है। पहले चरण के लिए वास्तविक कार्यान्वयन इसके साझेदारों यानी बीएसएनएल, पीजीसीआईएल और रेलटेल द्वारा किया जा रहा है। भारतनेट ई-गवर्नेंस सेवाओं, टेलीमेडिसिन, टेलीएजुकेशन, वित्तीय सेवाएं, ई-कॉमर्स और ई-मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। इससे पहुंच सेवा प्रदाताओं जैसे मोबाइल ऑपरेटरों, केबल टीवी ऑपरेटरों, आदि के लिए नए आयाम खुलेंगे, जिससे वे अगली पीढ़ी की सेवाएं शुरू कर सकेंगे और ई-कामर्स, आईटी आउटसोर्सिंग आदि के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। साथ ही समावेशी विकास के लिए ई-बैंकिंग, ई-हेल्थ और ई-एजुकेशन जैसी सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। इससे विभिन्न सेवाओं के वितरण में भी मदद मिलेगी, जैसे पंचायती स्तर पर स्थानीय आयोजना, प्रबंधन, निगरानी और सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत भुगतान जैसी सुविधाएं।

सेना की प्रचालनगत संचार व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए सरकार ने नेटवर्क फॉर स्पैक्ट्रम (एनएफएस) नाम की एक परियोजना शुरू की है। यह एक देशव्यापी सुरक्षित, बहु-सेवा प्रदाता और विशेष एवं प्रतिबद्ध त्रि-सेवाओं- ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट बैकबोन पर आधारित मल्टी प्रोटोका ॅल कन्वर्ज्ड नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क है। परियोजना का प्रभाव भारतीय सेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं पर पड़ेगा, जिसमें ध्वनि, आंकड़े और वास्तविक समय अनुसार वीडियो सेवाएं शामिल हैं। परियोजना का कार्यान्वयन बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है।

दूरसंचार क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को वांछित मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं जैसे (प) 2014-15 के केंद्रीय बजट में कुछ आयातित दूरसंचार उत्पादों पर 10 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क लगाना ताकि घरेलू विनिर्माताओं को समान सुविधाएं प्रदान की जा सकें और घरेलू दूरसंचार इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। (पप) विपरीत शुल्क ढांचे में सुधार और (पपप) 2015-16 के बजट में दूरसंचार ग्रेड के ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले एचडीपीई (हाई डेंसिटी पोलीएथीलीन) पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटा कर शून्य कर दिया गया ताकि देश में आॅप्टिकल फाइबर के विनिर्माण को बढावा दिया जा सके।

एम2एम संचार को मजबूत बनाने के लिए 12 मई, 2015 को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 'नेशनल टेलीकॉम एम2एम रोड मैप' नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रोड मैप दस्तावेज में विभिन्न एम2एम मानक शामिल करने, नीति की रूपरेखा तैयार करने और एम2एम का प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न नियामक उपाय अपनाए गए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय एम2एम परिदृश्य, प्रचलित संचार प्रौद्योगिकियों, मानकीकरण गतिविधियां और विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाने जैसे उपाय शामिल हैं।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अत्यंत आकर्षक बन गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एफडीआई इक्विटी के रूप में 2895 अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया जो 2012-13 (304 अमरीकी डॉलर) और वित्तीय वर्ष 2013-14 (1307 अमरीकी डॉलर) के एफडीआई इक्विटी निवेश के योग से भी अधिक था। यह पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक था।

विभिन्न बैंडों में स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार विभाग ने 2015 में स्पैक्ट्रम नीलामी आयोजित की। इसके लिए पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बोली प्रक्रिया अपनाई गई जिसके फलस्वरूप अब तक की सर्वाधिक नीलामी राशि 1,09,874 करोड़ रुपये प्राप्त हुई जबकि अनुमोदित आरक्षी मूल्य रुपये 80,277 करोड़ रखा गया था। इससे दूरसंचार क्षेत्र के सभी सहभागियों का विश्वास बहाल करने में मदद मिली।

पिछले एक वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप भारतीय दूरसंचार क्षेत्र जून 2014 से जून 2015 की अवधि में 644.4 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन दे सका, जो फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर हैं। इन सबको मिला कर भारत में 100.743 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन हैं और भारत का टेलीफोन नेटवर्क चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इनमें से 42.342 करोड़ टेलीफोन ग्रामीण क्षेत्रों में और 58.4 करोड़ टेलीफोन शहरी क्षेत्रों में हैं। देश में टेली-डेंसिटी यानी दूरसंचार घनत्व 80.02 प्रतिशत पर पहुंच गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-डेंसिटी 48.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 149.3 प्रतिशत है। इंटरनेट का विकास भी तेजी से हो रहा है। मार्च 2015 तक भारत में 30.235 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो अमरीका की आबादी के समान हैं।